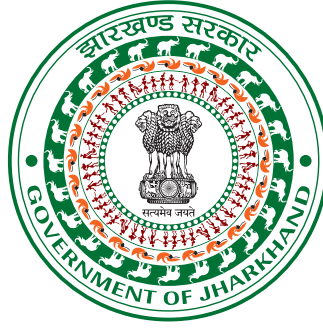




श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड



श्री राधाकृष्ण किशोर
माननीय वित्त मंत्री
झारखण्ड

श्री राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 24 फरवरी, 2026



श्री राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 24 फरवरी, 2026

माननीय अध्यक्ष महोदय,

!! जोहार !!

1. झारखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आपका और सम्पूर्ण सदन का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे संसदीय जीवन का यह दूसरा अवसर है, जब मैं झारखण्ड राज्य के अनुमानित आय और व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे यह पुनीत अवसर देने के लिए सम्पूर्ण सदन, राज्य की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतागण तथा राज्य के मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
2. मुझे ही नहीं, आज सम्पूर्ण सदन और राज्य की जनता को एक सामाजिक–राजनैतिक व्यक्तित्व की कमी खल रही है और वह व्यक्तित्व हैं – दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। वर्ष 2026–27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

कैसे भूल सकते हैं महापुरुषों को!

3. **अध्यक्ष महोदय,** हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? जिन्होंने देश के लिए अपना सबकुछ अर्पित कर झारखण्ड सहित देश की एकता और अस्मिता की रक्षा किया है। इस सदन की ओर से मैं वीर–भूमि झारखण्ड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुण्डा के साथ तिलका मांझी, बीर बुधू भगत, पोटो हो, सिदो कान्हु मुर्मू, चाँद–भैरव, फूलो–झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पाण्डे गणपत राय, नीलाम्बर–पीताम्बर और शेख भिखारी सहित सभी नाम–अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।

4. **अध्यक्ष महोदय,** हम झारखण्ड के रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं। प्रकृति ने हमें घने जंगलों, खूबसूरत पहाड़ियों, बहुमूल्य खनिज संपदाओं, शानदार झरनों का झारखण्ड प्रदेश के रूप में अनुपम उपहार दिया है। छोटानागपुर की रानी अर्थात् नेतरहाट अपने शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर बेतला राष्ट्रीय उद्यान एवं हजारीबाग अभयारण्य बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए बेहतरीन स्थान है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, रजरप्पा का सिद्धपीठ, गुमला का अंजनी धाम, ऐतिहासिक धरोहर राजा मेदिनीराय का पलामू किला, पारसनाथ की पहाड़ी और जैन मंदिर, राजमहल का जामा मस्जिद, रांची स्थित GEL चर्च, साहेबगंज का ऐतिहासिक श्री गुरुतेग बहादुर गुरुद्वारा तथा मसानजोर, मैथन, तिलैया, मलय, चांडिल डैम इत्यादि झारखण्ड को भारत के मानचित्र पर स्थापित करते हैं।
5. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, आदिवासी संस्कृति का रक्षक और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अलग राज्य बनने का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन तथा जनहितकारी उपयोग सुरक्षित करना था। झारखण्ड की विकास यात्रा संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है। बजट केवल आम व्यय का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। यह बजट समावेशी, सतत और जनकल्याणकारी विकास को समर्पित है तथा राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला है। झारखण्ड केवल खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य नहीं है, बल्कि यह विविध जनजातीय परंपराओं, लोक संस्कृति, सामुदायिक जीवन मूल्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की बेमिसाल परंपरा का प्रतीक

है। यहां की धरती पर परिश्रम, सहभागिता और सामाजिक समरसता की भावना पीढ़ियों से प्रवाहित होती रही है।

6. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन की राज्य सरकार, भावनाओं और संवेदनशीलता के साथ जन भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं एक मजबूत और आत्मनिर्भर झारखण्ड बनाने के लिए हृदय से प्रतिबद्ध है।
7. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में झारखण्ड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरु के द्वारा बताये गए समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। हम झारखण्ड राज्य के निर्माण के उद्देश्यों – जन कल्याण और भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर झारखण्ड – को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकायें। हम न झुके हैं, ना झुकेंगे, हमें तो इन चार पंक्तियों पर भरोसा है—

“ किसी के पैर में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है,

अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें।”

8. **अध्यक्ष महोदय,** अबुआ राज की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में इण्डिया गठबंधन की सरकार अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गये निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कृत संकल्पित है।

9. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022–23 से नए प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें विकास के विभिन्न प्रक्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ-साथ झारखण्ड की आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी की वर्ष दर वर्ष व्यापक भागीदारी रही है। बजट पूर्व कार्यशालाओं एवं आम जनता के सुझावों से सरकार के सभी विभाग लाभान्वित हो रहे हैं तथा एक समावेशी बजट के गठन में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में “हमर अपन बजट”, 2023–24 एवं 2024–25 में “हमीन कर बजट”, 2025–26 में “अबुआ बजट” एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में “अबुआ दिशोम बजट” गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है।
10. **अध्यक्ष महोदय,** मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार समाज में हाशिये पर खड़े लोग, बेरोजगार युवक, फसलों के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में वृद्धि, आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने को लेकर संवेदनशीलता के साथ बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन झारखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए “बहुत कुछ” करना अकेले सिर्फ राज्य के बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा झारखण्ड जैसे पिछड़े राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है। लेकिन मुझे दुःख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, परंतु अभी तक केंद्रीय करों में झारखण्ड की हिस्सेदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये झारखण्ड को अप्राप्त है। इसी तरह अनुदान की राशि

के मद में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 11 हजार करोड़ रुपये अभी तक झारखण्ड को नहीं मिला है। संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत केंद्र से मिलने वाली राशि झारखण्ड को समय पर नहीं मिल पाती है। अनुदान की राशि के मद में विगत पांच वर्षों से निरंतर कटौती की जा रही है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार की अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण झारखण्ड के ऊपर घोर आर्थिक बोझ पड़ रहा है अथवा पड़ने वाला है। माल एवं सेवा कर के दर युक्तिकरण से झारखण्ड राज्य को प्रतिवर्ष 4 हजार करोड़ रुपये की क्षति हो रही है। इसी तरह मनरेगा का परिवर्तित नाम VB-G RAM G योजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60:40 राशि के बंटवारे से झारखण्ड को लगभग प्रतिवर्ष 5 हजार 640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। इसी तरह अनेकों प्रयास करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोल कंपनियों के पास बकाया राशि 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये झारखण्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

बजट उपस्थापन के अवसर पर हम उन्हें यह सन्देश देना चाहते हैं कि—

“किसी के पैर खींचना आसान होता है,

इसके लिए न जहन चाहिए, न ही जिगर।

मगर किसी का हाथ थामना, उसे ऊपर खींचना, उसके हौसले को मजबूत करना,

यह वही अमल है जो इंसान को सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि महान बनाता है।”

11. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केन्द्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अतः जहाँ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्द्धन समिति बनाकर राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है, वहीं अन्य स्रोतों यथा— Public Private Partnership, CSR एवं अन्य बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से Funding प्राप्त करने हेतु एजेन्सियों को चिन्हित किया जा रहा है।
12. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड सरकार द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF), 2026 में पहली बार भाग लेकर राज्य की वैश्विक पहचान को मजबूती से स्थापित किया गया तथा हरित औद्योगिकीकरण एवं समावेशी, सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया गया। इसके फलस्वरूप, झारखण्ड Sustainable Green Industry, Critical Minerals & Forest Based Value Chain और पारंपरिक अर्थव्यवस्था आधारित विकास के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है।
13. **माननीय महोदय,** आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी के पहल पर राज्य में बहुप्रतिक्षित **PESA (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) अधिनियम इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 02.01.2026 को लागू किया गया है।** इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाटों का प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं में लाभुकों का चयन, हाट—बाजार का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है।

14. **अध्यक्ष महोदय,** भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (I) सह पठित 243 (Y) के अधीन गठित पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधायन (Devolution) के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्व-कर राजस्व (Net Own Tax Revenue Receipts - NOTRR) का 4 (चार) प्रतिशत के रूप में तय किया गया है। तदनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अनुदान की कुल राशि 1172 करोड़ 66 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
15. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की आर्थिक-संस्कृति मुख्यतः खेती-किसानी पर आधारित होने के कारण हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, कृषि में समग्र विकास को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय में वृद्धि करना रही है। महोदय, इसका असर भी दिखने लगा है। अद्यतन आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पी०एल०एफ०एस०) के अनुसार कृषि प्रक्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत गत तिमाही में 44.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गया है।
16. **मान्यवर,** सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हेमन्त सरकार कृत संकल्पित है। इस सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने धनबाद में 2 तथा पलामू, लातेहार एवं गढ़वा में 1-1 कुल 5 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नये उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार के विशेष पहल पर शहीद के

आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी।

17. **महोदय,** झारखण्ड में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अंतर्गत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीक की मदद दी जाएगी और ऑफलाईन एवं ऑनलाईन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए **25 करोड़** का बजटीय उपबंध किया गया है।
18. **महोदय,** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केन्द्रीय सेक्टर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परन्तु केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रांश मद की राशि कम उपलब्ध करायी जा रही है, फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केन्द्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश मद में लगभग **18 हजार 273 करोड़** रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी विभाग केन्द्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करेंगे।
19. **महोदय,** विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उनका ध्यान रखा, जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना,

सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मराठ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती-लुंगी-साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने शुरू की हैं। साथ ही, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग तीन गुणा की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई हैं।

20. **अध्यक्ष महोदय,** मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में राज्य का आर्थिक विकास दर 12 प्रतिशत (Constant Price) था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7.2 प्रतिशत (Constant Price) रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5 प्रतिशत (Constant Price) रहा तथा वर्ष 2024-25 में 7.02 प्रतिशत (Constant Price) रहा। वर्ष 2025-26 में इसके 7.72 प्रतिशत (Constant Price) पर रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में आर्थिक विकास दर 2011-12 के Constant Price पर 6.90 प्रतिशत एवं वर्तमान मूल्य (Current Prices) पर 10.03 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

21. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा को 2.81 प्रतिशत रखने में सफलता हासिल की है। राज्य के Debt-GDP Ratio में भी सुधार हुआ है। यथा— वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 30.2 प्रतिशत था,

वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में क्रमशः 27.0 तथा 25.3 प्रतिशत रहा तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में क्रमशः 25.2 प्रतिशत एवं 25.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

22. **अध्यक्ष महोदय,** दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने राजस्व आय (कर और गैर कर राजस्व) में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019–20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय **25,521 करोड़ (25 हजार 5 सौ 21 करोड़)** रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में **42,732.70 करोड़ (42 हजार 732 करोड़ 70 लाख)** रुपये हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में **66,700 करोड़ (66 हजार 700 करोड़ लाख)** रुपये रहने का अनुमान है।
23. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत पाँच वर्षों में स्थापना–व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाय तो यह वित्तीय वर्ष **2019–20 में 47:53** था (क्रमशः 33 हजार 145 करोड़ 37 लाख एवं 52 हजार 283 करोड़ 63 लाख) जो वित्तीय वर्ष **2026–27 में 36:64** (क्रमशः 57 हजार 669 करोड़ एवं 1 लाख 891 करोड़) प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
24. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूँजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में **37,708.10 करोड़ (37 हजार 708 करोड़ 10 लाख)** रुपये पूँजीगत परिव्यय का आकलन

किया गया है, जो पूँजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत वृद्धि है।

25. **अध्यक्ष महोदय**, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबन्धन किया गया है।
26. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में सम्भावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा Sinking Fund में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अबतक इसमें लगभग 2,801 करोड़ (2 हजार 801 करोड़) रुपये का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिये ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ-साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। इस वर्ष इसमें 654 करोड़ रुपये का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है।
27. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य के आय विशेषकर खनन राजस्व के भविष्य में कमी होने के कारण राज्य के दायित्वों में प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2025–26 में 832 करोड़ रुपये निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में 1209 करोड़ रुपये का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है।
28. **अध्यक्ष महोदय**, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पाँच जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने

का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए **1,58,560 करोड़ (1 लाख 58 हजार 560 करोड़)** रुपये का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो गत वर्ष से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है।

29. **अध्यक्ष महोदय**, वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजस्व व्यय के लिए **1,20,851.90 करोड़ (1 लाख 20 हजार 851 करोड़ 90 लाख)** रुपये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 9.2 प्रतिशत अधिक है। पूँजीगत व्यय अन्तर्गत गत वर्ष के बजट पर 8.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ **37,708.10 करोड़ (37 हजार 708 करोड़ 10 लाख)** रुपये का प्रस्ताव है।
30. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए **32,055.83 करोड़ (32 हजार 55 करोड़ 83 लाख)** रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए **67,459.54 करोड़ (67 हजार 459 करोड़ 54 लाख)** रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए **59,044.63 करोड़ (59 हजार 44 करोड़ 63 लाख)** रुपये उपबंधित किये गये हैं।
31. **अध्यक्ष महोदय**, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से **46,000 करोड़ (46 हजार करोड़)** रुपये तथा गैर कर राजस्व से **20,700 करोड़ (20 हजार 700 करोड़)** रुपये केन्द्रीय सहायता से **18,273.66 करोड़ (18 हजार 273 करोड़ 66 लाख)** रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में **51,236.38 करोड़ (51 हजार 236 करोड़ 38 लाख)** रुपये, लोक ऋण से **22,049.96 करोड़ (22 हजार 49 करोड़ 96 लाख)**

- रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से **300 करोड़** रुपये होने का अनुमान है।
32. वर्ष 2026–27 में राजकोषीय घाटा **13,595.96 करोड़ (13 हजार 595 करोड़ 96 लाख)** रुपये होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित GSDP का 2.18 प्रतिशत है।
33. वर्तमान मूल्य पर झारखण्ड का GSDP वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग **5 लाख 16 हजार करोड़ रुपये** रहा। सरकार का प्रयास होगा कि अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना किया जाय। इसके लिए हमें वर्तमान मूल्य पर करीब 14 प्रतिशत का विकास करना होगा। स्थिर मूल्य पर यह करीब 9 से 10 प्रतिशत की विकास दर होगी।
34. **महोदय**, कोविड के बाद के वर्षों में (2021–22 से 2025–26) मौजूदा कीमत पर (Current Prices) राज्य के GSDP में 14.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है।
35. वर्ष 2011–12 से 2024–25 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर GSDP में 9.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान वर्ष 2015–16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019–20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020–21 में कोविड-19 महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन ग्यारह वर्षों में से पाँच वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.1 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ा।
36. सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी GSDP सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखण्ड में भी मौजूद हैं। झारखण्ड एक संसाधन

संपन्न राज्य है। देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज भंडार इसी राज्य में स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 34 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

37. राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्होंने देश भर में कई परियोजनाओं और स्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी कि झारखण्ड में ही इन्हें अधिक-से-अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाय।
38. **मान्यवर**, 14.1 प्रतिशत की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके, बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर (बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थान आदि) का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र

39. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य की आर्थिक-संस्कृति मुख्यतः खेती-किसानी पर आधारित होने के कारण हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, कृषि में समग्र विकास को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय में वृद्धि करना रही है। महोदय, इसका असर भी दिखने लगा है। अद्यतन आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पी०एल०एफ०एस०) के

अनुसार कृषि प्रक्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत गत तिमाही में 44.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गया है।

40. **आदरणीय महोदय,** वित्तीय वर्ष 2023–24 में लागू बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग **7 लाख 2 हजार 50** किसानों को आच्छादित किया गया। इस योजनान्तर्गत बजटीय उपबंध को गत वित्तीय वर्ष के 95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026–27 में **145 करोड़** रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।
41. **आदरणीय महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राईस फ़ैलो उपयोजना एवं जलनिधि उपयोजना अन्तर्गत सरकारी/निजी तालाबों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसे जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 में बंजर भूमि राईस फ़ैलो उपयोजना एवं जलनिधि उपयोजना अन्तर्गत कुल **475 करोड़ 50 लाख** रुपये का बजट प्रस्ताव है।
42. **माननीय महोदय,** कृषि समृद्धि योजना झारखण्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी राज्य योजना है, जो कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाये जा रहे जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा स्रोत के स्थान पर सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाईयों को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन लागत को कम करने के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस हेतु **75 करोड़** रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।

43. **आदरणीय महोदय,** खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अन्तर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पम्प सेट, रीपर, ट्रान्सप्लान्टर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में **80 करोड़** रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
44. **आदरणीय महोदय,** सुखाड़ की स्थिति से निबटने हेतु संचालित झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन अन्तर्गत किसानों को लगातार आच्छादित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन योजनान्तर्गत लगभग 65 हजार किसानों का फसल सर्वेक्षण किया गया है, जिसके पूर्ण होने के बाद किसानों को अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026–27 योजना को जारी रखते हुए **25 करोड़** रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
45. **आदरणीय महोदय,** राज्य में गन्ना, जूट एवं अन्य नकदी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। इस हेतु पुरानी योजना को 'नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना' पुनर्नामित करते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 में **19 करोड़ 88 लाख** रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।
46. **आदरणीय महोदय,** उद्यानिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने, कृषकों की आय में वृद्धि करने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से राज्य उद्यान विकास की योजना को आगे बढ़ाते हुए इस योजना अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती, फूल की खेती, कृषक प्रशिक्षण, सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजना, शहरी फार्मिंग योजना, गोधन न्याय योजना, जैविक प्रमाणीकरण योजना, हाईटेक पार्क, लाह की खेती आदि पर

वित्तीय वर्ष 2026–27 में **245 करोड़ 80 लाख** रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

47. **अध्यक्ष महोदय,** पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में **मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना** अन्तर्गत बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना, बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना, ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख चूजा वितरण योजना, भेड़पालन की योजना, उद्यमी पशुपालकों की योजना, दुधारु गाय वितरण योजना, कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना, तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरण योजना, दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन अनुदान योजना आदि पर वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग कुल **481 करोड़ 35 लाख** रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत ही गिरिडीह एवं सरायकेला में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरी तथा राँची में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट एवं उच्च क्षमता के मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना हेतु झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
48. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिरसा–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए **400 करोड़** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

49. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रथम चरण में एक लैंप्स/पैक्स में कॉपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह-सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
50. **अध्यक्ष महोदय,** वर्तमान में लैंप्स/पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 एम०टी० क्षमता के 48 गोदाम, 500 एम०टी० क्षमता के 24 गोदाम एवं World's Largest Grain Storage Plan in Co-operative योजनान्तर्गत 2,500 एम०टी० क्षमता के 72 गोदामों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसपर लगभग कुल **160 करोड़ 26 लाख** रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक लैंप्स/पैक्स में कॉपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह-सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **162 करोड़ 20 लाख 90 हजार** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
51. **अध्यक्ष महोदय,** चालू वित्तीय वर्ष के सितंबर माह तक 1,70,400 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत जलाशय मत्स्य का विकास, फीड बेस्ड फिशरीज विकास, मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन, केज कल्चर विस्तार, बायोप्लॉक तालाब निर्माण आदि पर **106 करोड़** रुपये के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है। उक्त समेकित मत्स्य विकास योजना के तहत ही डोरण्डा फिश पार्क एवं मत्स्य निदेशालय प्रांगण सहित बटन तालाब स्थित उपलब्ध भूमि को Centre of Excellence के रूप में विकसित किए जाने का प्रावधान भी है।

52. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4 हजार 884 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास

53. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2025–26 में महात्मा गाँधी नरेगा योजना अन्तर्गत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताहांत तक 10 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है।
54. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिसमें लाभार्थियों को पाँच किस्त में **2,00,000 /— (दो लाख)** रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजनान्तर्गत 2024–25 तक के लिए अबुआ आवास हेतु निर्धारित लक्ष्य 6 लाख 50 हजार के विरुद्ध अब तक कुल 6 लाख 33 हजार 106 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 1 लाख 88 हजार 849 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण कराने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत कुल **4,100 करोड़** रुपये का आगामी बजट में उपबंध प्रस्तावित है।
55. **आदरणीय महोदय,** सखी मंडलों के उत्पादों को उचित मूल्य एवं आर्थिक सहायता देने तथा वर्ष भर बाजार उपलब्ध कराने के लिए पलाश-ब्रांड के

तहत विपणन कराया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026—27 में पलाश मार्ट पर **66 करोड़** रुपये के व्यय का प्रस्ताव है।

56. **आदरणीय महोदय**, वित्तीय वर्ष 2025—26 में 2 हजार सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि तथा 35 हजार स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट हेतु बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध 4 हजार से अधिक सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा 1 लाख 97 हजार स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट हेतु बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान की जा चुकी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में महिला किसान सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं पर **70 करोड़** रुपये के बजटीय उपबंध का प्रावधान किया गया है।
57. **वर्ष 2026—27 में ग्रामीण विकास के लिए 12 हजार 346 करोड़ 90 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।**

जल संसाधन

58. **अध्यक्ष महोदय**, वृहद् एवं मध्यम सिंचाई प्रक्षेत्र में वर्ष 2025 में लगभग 4 लाख 48 हजार हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराया गया है। इस प्रक्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026—27 में **1137 करोड़ 10 लाख** रुपये का योजना प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें नई सिंचाई परियोजना का निर्माण एवं पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य है। पूर्ण एवं अपूर्ण वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए **121 करोड़** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
59. **अध्यक्ष महोदय**, पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड अन्तर्गत कोल्हुआ ग्राम में अमानत नदी पर अमानत बराज योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2003 में प्रारंभ

कर वर्ष 2011 तक कराया गया। तत्पश्चात, वन भूमि अपयोजन एवं भू-अर्जन का कार्य अपूर्ण रहने के कारण योजना का कार्य बाधित रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा योजना को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत भू-अर्जन को कम करने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत वितरणियों का कार्य भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से कराया जायेगा। योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए अगले तीन वर्षों में योजना का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा, जिससे पलामू जिला के पांकी, पाटन, तरहसी एवं मनातू प्रखण्ड के 12,856 हे० भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

60. **अध्यक्ष महोदय**, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक 203 चेकडैम, 3 वीयर एवं 41 मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण कर लगभग 16 हजार 199 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा सृजित/पुनर्जीवित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए एवं चालू लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण आदि कार्यों के लिए **215 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
61. **सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 में जल संसाधन के लिए 2 हजार 714 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।**

पंचायती राज

62. **अध्यक्ष महोदय**, शत-प्रतिशत राज्य योजना मद अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत सचिवालय सुदृढीकरण योजना, विभिन्न भवन परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मती/जीर्णोद्धार, सामुदायिक सेवा

केंद्र तथा पंचायत ज्ञान केंद्र आदि पर कुल **209 करोड़** के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

63. **अध्यक्ष महोदय**, वित्तीय वर्ष 2026–27 में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान मद में **1 हजार 340 करोड़** रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है। उक्त राशि से संबंधित संस्था 30 (तीस) प्रतिशत जलापूर्ति पर, 30 (तीस) प्रतिशत स्वच्छता पर एवं शेष 40 (चालीस) प्रतिशत का व्यय स्थानीय आवश्यकता की योजनाओं पर कर सकेगी।
64. **माननीय महोदय**, वित्तीय वर्ष 2026–27 में पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अनुदान मद में अनुमोदित राशि के विरुद्ध **216 करोड़** रुपये की राशि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।
65. **पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2026–27 में 2 हजार 283 करोड़ 25 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

66. **अध्यक्ष महोदय**, वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, दिव्यांगजनों, भिक्षुकों तथा समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।
67. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य सरकार सशक्त एवं समर्थ राज्य तथा समाज निर्मित करने के निमित्त राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और शिक्षित बनाने के निमित्त 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को **झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना** का लाभ दे रही है। इस योजनान्तर्गत

प्रति महिला प्रति माह 2 हजार 5 सौ रुपये की दर से भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में **14 हजार 65 करोड़ 57 लाख** रुपये का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

68. **अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना** के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किये गये हैं, किन्तु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, HIV/AIDS से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रांसजेन्डरों/तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ-साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति/जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **3 हजार 517 करोड़ 23 लाख** रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग **34 लाख लाभार्थी** आच्छादित होंगे।
69. **अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना** के मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल **1,463 करोड़ 58 लाख** रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है, जिससे लगभग 12,00,000 (बारह लाख) लोगों को पेंशन दिया जा सकेगा।
70. **अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार असहाय एवं वंचित वर्ग को ठंड के प्रभाव से बचाने हेतु 9 लाख से अधिक इकाई कंबल बाँटने के अपने कल्याणकारी योजना पर व्यय हेतु 56 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।**

71. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभाग द्वारा राज्य संसाधन से 1,100 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण सम्पादित कराया जायेगा तथा इसके लिए रु० **176.00 करोड़** का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।
72. **अध्यक्ष महोदय,** भविष्य के निर्माता आज के बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास सुनिश्चित करने तथा इन्हें कुपोषण के दुष्चक्र से मुक्त रखने के निमित्त 2 लाख 60 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं, 06 वर्ष तक के 21 लाख 34 हजार से अधिक बच्चों को वर्ष के 300 दिनों तक उच्च गुणधर्म तथा उच्च ऊर्जा युक्त पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में **829 करोड़ 99 लाख रुपये** का बजटीय उपबंध पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित किया गया है।
73. **माननीय महोदय,** आंगनबाड़ी केन्द्र में पाठशाला पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03–06 वर्ष के 10 लाख 76 हजार से अधिक बच्चों को युनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, पठन-पाठन एवं लेखन सामग्री तथा केन्द्र में बैठने हेतु टेबुल-कुर्सी की सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में रुचिकर वातावरण मिलेगा तथा वे शिक्षा एवं पोषण प्राप्ति हेतु प्रेरित रहेंगे। इस कार्यक्रम पर आगामी वर्ष में कुल **260 करोड़ 17 लाख** का व्यय प्रस्तावित है।
74. **माननीय महोदय,** आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारु संचालन एवं इस हेतु इनमें आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, पोषण सखियों को सम्मानजनक पारिश्रमिक एवं सेवा-सुविधाएँ सहित केन्द्रों में समुचित विद्युत संयोजन, LPG संयोजन एवं Refilling, केन्द्र की स्थानीय आवश्यकता हेतु Untied Fund

इत्यादि संबंधी स्थापना व्यय हेतु केन्द्र प्रायोजित आंगनबाड़ी सेवाएँ तथा राज्य योजना अन्तर्गत क्रमशः **418 करोड़ 84 लाख** रुपये एवं **619 करोड़ 83 लाख** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

75. **माननीय महोदय,** राज्य सरकार द्वारा 43 वृद्धाश्रमों, दिव्यांग आवासीय विद्यालयों एवं स्पैष्टिक विद्यालयों के संचालन कर इसके लाभार्थियों को समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं इनके गरिमामयी जीवन-यापन को सुनिश्चित कराने हेतु **25 करोड़** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित कर रहा है। इसके तहत आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, संसाधनों का अधिष्ठापन/व्यवस्था तथा लाभार्थियों के आवासन-भोजन-वस्त्र एवं पठन-पाठन की उपलब्धता सहित केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।
76. **अध्यक्ष महोदय,** 14-18 वर्ष की 1.41 लाख किशोरियों को भी पूरक पोषणाहार का निरंतर वितरण कर कुपोषण तथा रक्तअल्पतता के पीढ़ीगत संभावनाओं को निरस्त करने हेतु **41 करोड़ 26 लाख** रुपये का बजटीय उपबंध किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के तहत प्रस्तावित किया गया है।
77. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 495 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण पर कुल **55 करोड़ 32 लाख** रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
78. **अध्यक्ष महोदय,** महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में 22 हजार 995 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

शिक्षा प्रक्षेत्र

79. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार स्कूली शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु निरंतर सजग, संवेदनशील एवं प्रयत्नशील है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सभी सूचकांकों पर गहनता एवं सजगता के साथ योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।
80. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ किया गया है एवं इसका विस्तार किया जा रहा है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन प्रारंभ करते हुए 222 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन आदर्श विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **182 करोड़ 60 लाख** का बजटीय उपबंध किया गया है।
81. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के कुल 34,847 प्रारंभिक विद्यालयों, 1,711 माध्यमिक विद्यालयों एवं 1,157 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 70 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अन्तर्गत 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा 26 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित है।
82. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में अबतक कुल 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु 1,197 लैब अधिष्ठापित किये गये हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न 11 ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, जबकि अन्य 888 लैब की अधिष्ठापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 1,58,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

83. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य के 2,495 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. कार्यक्रम के तहत डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 2,610 मध्य विद्यालयों को इससे जोड़ा गया है।
84. **मान्यवर**, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु सभी अनिवार्य पहल की जा रही है। इसके अन्तर्गत विशेष रूप से राज्य केन्द्रित पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण हेतु पाठ्यक्रम का विकास किया गया है। कक्षा 01 से कक्षा 02 की नई पाठ्य-पुस्तक तैयार कर ली गयी है एवं शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इसे विद्यार्थियों के बीच वितरित किया जाना है।
85. **मान्यवर**, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ठोस रणनीति तैयार कर प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष 50 घंटे के प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जा रही है। JCERT के स्तर पर इस हेतु रणनीति तैयार करते हुए माह फरवरी, 2025 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। अबतक लगभग 40 हजार शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है।
86. **अध्यक्ष महोदय**, नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर 03 विद्यालय भवन का निर्माण कार्य मसलिया, दुमका, खूंटपानी, चाईबासा एवं बोकारो के नवाडीह में संचालित है।
87. **मान्यवर**, राज्य के सभी जिलों में Centre of Art District Library के संचालन की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गयी है। यह पुस्तकालय सभी सुविधायुक्त होगा तथा 500 पाठकों के लिए व्यवस्थित होगा।
88. **मान्यवर**, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखण्ड के सभी राजकीय पोलिटेकनिक (17 राजकीय पोलिटेकनिक एवं 06 नवनिर्मित पोलिटेकनिक) को J-PRAGATI Scheme (Jharkhand Polytechnic Revamping for Advanced Graduate and

Innovation led Technical Institution) के तहत IIT एवं NIT के तर्ज पर Jharkhand Institute of Technology (JhIT) के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

89. **महोदय, UTTHAN** (Uplifting of Tribal and Tana Bhagat Holistic Advancement and Nurturing) योजना के तहत राज्य के आदिम जनजाति तथा टाना भगत के आश्रितों के शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ऐसे 60 छात्रों को प्रतिवर्ष झारखण्ड रक्षा विश्वविद्यालय, राँची में Police Administration and Integrated Security Management संकाय में 03 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
90. **माननीय महोदय,** उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य के **चतरा जिला मुख्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।** उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों जहाँ नए महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है, वहाँ महाविद्यालय की स्थापना कर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में Job Oriented Courses की पढ़ाई करायी जाएगी। प्रथम चरण में 07 जिलों में 12 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
91. **मान्यवर,** राज्य में STEM Education (Science, Technology, Engineering, Maths) को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा।
92. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16 हजार 251 करोड़ 43 लाख रुपये तथा उच्च एवं

तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 564 करोड़ 45 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

93. **अध्यक्ष महोदय,** कैंसर रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य योजना बजट के अंतर्गत 200 करोड़ की राशि कर्णांकित की जाएगी।
94. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार राज्यवासियों को त्वरित, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं।
95. **मान्यवर,** मान्यवर, विगत दस वर्षों में झारखण्ड में कैंसर रोग का फैलाव तीव्रता से हुई है। इसी प्रकार महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का प्रभाव भी अत्यधिक संख्या में हुई है। कैंसर रोग की रोकथाम के लिए झारखण्ड के सभी पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में PET & CT Scan मशीन का अधिष्ठापन किया जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में ही ब्रेस्ट कैंसर रोग की पहचान कर लिए जाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 24 जिला सदर अस्पताल में मैमोग्राफी मशीन स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कैथलैब की स्थापना की जाएगी।
96. **मान्यवर,** प्रथम चरण में, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा एवं खूँटी सदर अस्पताल को PPP Mode में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। दूसरे चरण में, लातेहार, साहेबगंज एवं सरायकेला-खरसावाँ में सदर अस्पतालों को PPP Mode में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का रूप दिया जाएगा।

97. **मान्यवर,** अगले वर्ष रिम्स सहित सरकारी मेडिकल कॉलेज में 220 MBBS सीट में बढ़ोतरी तथा आगामी 4 वर्षों में MBBS सीट को 1,030 से बढ़ाकर दुगुना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में PG सीट 225 को अगले वर्ष 325 तथा 4 वर्षों में 750 करने का लक्ष्य है।
98. **मान्यवर,** राज्य में 750 अबुआ दवाखाना खोले जाने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से लोगों में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध करायी जाएगी।
99. **माननीय महोदय,** शत-प्रतिशत राज्य योजना से क्रियान्वित मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना तथा मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार सुनिश्चित कराया जा रहा है।
100. **अध्यक्ष महोदय,** स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण के लिए 7 हजार 990 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पेयजल एवं स्वच्छता

101. **अध्यक्ष महोदय,** जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62 लाख 55 हजार ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन (FHTC) के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 34 लाख 46 हजार परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।
102. **अध्यक्ष महोदय,** दूर-दराज के क्षेत्र जो जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं, अथवा आंशिक रूप से आच्छादित हैं तथा योजनाओं के पूर्ण होकर चालू होने में विलम्ब की संभावना के कारण राज्य के कुल 4,351 ग्राम पंचायतों में लगभग 43 हजार 510 अदद नलकूपों के अधिष्ठापन की स्वीकृति

दी गयी है। अब तक स्वीकृत नलकूपों में से 35 हजार 581 (लगभग 82 प्रतिशत) नलकूपों का अधिष्ठापन किया गया है।

103. **महोदय**, स्वच्छता के क्षेत्र में लगभग सभी ग्रामीण घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। नवनिर्मित घरों तथा वैसे घरों, जिनमें शौचालयों की सुविधा नहीं है, में शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है।
104. **अध्यक्ष महोदय**, वर्ष 2026–27 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 5 हजार 194 करोड़ 53 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

105. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को बोनस तथा मिलर को इन्सेंटिव भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित किया गया है।
106. **मान्यवर**, शत-प्रतिशत राज्य योजना के अधीन दाल वितरण योजनांतर्गत लाभुकों को प्रतिमाह एक किलोग्राम चना दाल तथा नमक वितरण योजनांतर्गत लाभुकों को प्रतिमाह एक किलोग्राम नमक वितरण सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में **720 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।
107. **मान्यवर**, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए **560 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

108. **महोदय**, शत-प्रतिशत राज्य योजना के अधीन संचालित धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना अंतर्गत **600 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।
109. **मान्यवर महोदय**, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जनवितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन का Realtime Tracking किया जाएगा। इससे खाद्यान्न की कालाबाजारी पर प्रतिबंध संभव हो सकेगा।
110. वर्ष 2026-27 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हजार 887 करोड़ 27 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

111. **अध्यक्ष महोदय**, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 4 लाख 1 हजार 739 निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया गया है।
112. **अध्यक्ष महोदय**, ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 98.17 लाख झारखण्ड के असंगठित श्रमिकों का निबंधन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक 23 लाख 53 हजार 853 निबंधित असंगठित कर्मकारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु 61 करोड़ 21 लाख रुपये के समतुल्य योजनाओं का लाभ दिया गया है।
113. **अध्यक्ष महोदय**, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 56,998 लाभुकों को लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त साइकिल सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, मृत्यु

दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि योजना, विवाह सहायता योजना आदि में लाभ दिया जा रहा है।

114. **अध्यक्ष महोदय,** प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाईन किया जा रहा है तथा इनके कल्याण की योजनाएँ चलायी जा रही हैं। अबतक 2 लाख 18 हजार 942 प्रवासी मजदूरों का निबंधन किया जा चुका है।
115. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के 06 चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से AI (Artificial Intelligence) विषय पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने की योजना है।
116. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2025–26 में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 265 भर्ती कैम्पों एवं 89 रोजगार मेलों का आयोजन कर 13 हजार 408 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया।
117. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसायटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अबतक कुल 6 लाख 35 हजार 150 युवा-युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 4 लाख 92 हजार 966 प्रमाणित हुए हैं, जिसमें से 3 लाख 11 हजार 400 को जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं।
118. **मान्यवर,** वर्ष 2026–27 में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए 1 हजार 168 करोड़ 73 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

119. **अध्यक्ष महोदय,** छात्रावासों का निर्माण योजनांतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख

शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है।

120. **अध्यक्ष महोदय,** मराठ्. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से युनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्दन आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स/एम०फिल० डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना से अब अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी आच्छादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजनान्तर्गत 24 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है तथा अब इस योजना के लाभार्थी छात्र-छात्राओं की संख्या दोगुनी वृद्धि कर 50 कर दी गयी है।
121. **मान्यवर,** राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के वर्ग 8 में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में शैक्षणिक निरंतरता को प्रोत्साहित करने एवं ड्रॉप आउट रेट (छीजन) रोकने के उद्देश्य से छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजनान्तर्गत 136 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध करने का प्रस्ताव है।
122. **मान्यवर,** जनजाति समुदायों के सतत् विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं शोध के लिए जमशेदपुर (गालूडीह-घाटशिला) में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने को मंजूरी दी गई है। यह जनजातीय समुदायों के

समृद्ध सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को संरक्षित करने का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा।

123. **मान्यवर,** अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के कल्याण से जुड़ी छात्रवृत्ति योजनाएँ संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस हेतु 1,216 करोड़ की राशि के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।
124. **मान्यवर,** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 हजार 568 करोड़ 19 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

125. **माननीय महोदय,** भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है।
126. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणियों में अवस्थित प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों में इको-टूरिज्म का विकास कार्य, मुख्यमंत्री जन-वन योजना, कैम्पा योजना तथा लघुवन पदार्थ का उन्नयन योजना आदि के माध्यम से वन क्षेत्र का कार्य किया जा रहा है।
127. **माननीय महोदय,** लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत **पलामू वन प्रमंडल के कुन्दरी लाह फॉर्म का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किए जाएंगे,** ताकि लाह उत्पादन में वृद्धि हो सके एवं स्थानीय ग्रामीणों को आय के साथ-साथ रोजगार का सृजन हो सके।

128. **अध्यक्ष महोदय,** इको-टूरिज्म योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार एवं आय वृद्धि के साधन उपलब्ध कराने हेतु सारण्डा वन प्रमंडल में नोवामुण्डी पार्क, पाकुड़ वन प्रमंडल में फॉसिल पार्क एवं जैव विविधता पार्क, गुमला वन प्रमंडल में अंजन धाम इको पार्क तथा चाकुलिया इकोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की सुविधा एवं स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।
129. **अध्यक्ष महोदय,** विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2.40 करोड़ पौधों का रोपण किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग 2.60 करोड़ पौधों का रोपण किये जाने का लक्ष्य है, जो कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा वनभूमि पर रोपित होंगे।
130. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2026–27 में वन विभाग के लिए 1 हजार 544 करोड़ 75 लाख हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है।

पथ निर्माण

131. **अध्यक्ष महोदय,** आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, वरन् यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लम्बाई 5 हजार 400 कि०मी० थी, जो अब बढ़कर 15 हजार 66 कि०मी० हो गई है। पथों का घनत्व वर्ष 2025–26 के प्रारम्भ में 186.00 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 189.03 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
132. **मान्यवर,** पथ-घनत्व की वृद्धि के साथ राज्य के महत्वपूर्ण सड़कों के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने हेतु सड़कों को फोर लेन में

परिणत करने एवं फ्लाई ओवर बनाने का कार्यक्रम व्यापक रूप से लिया गया है। इसमें राजधानी राँची के साथ-साथ राज्य के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से नए-नए फ्लाई ओवर एवं फोर लेन के निर्माण का प्रस्ताव है।

133. **मान्यवर,** पथ निर्माण विभाग के पथों को उन्नत अवस्था में संधारित करने हेतु क्षतिग्रस्त पथों का IRQP (Improvement of Riding Quality Programme) का प्रस्ताव है।
134. **मान्यवर,** राज्य के पथों पर स्थित पुराने, क्षतिग्रस्त, Distressed एवं सड़क यातायात में Bottle neck साबित हो रहे पुलों के स्थान पर नये उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के तहत नये पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है।
135. **अध्यक्ष महोदय,** भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा सड़क-रेलमार्ग की सुरक्षा हेतु Level Crossing के Elimination का निर्णय लिया गया है। पथ निर्माण विभाग एवं रेल मंत्रालय के पारस्परिक समन्वय से विभिन्न Road Overbridge निर्माण का प्रस्ताव है।
136. **माननीय महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026-27 में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत पथों के घनत्व को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य करने के निर्धारित लक्ष्य के क्रम में विभागीय स्वामित्व अधीनस्थ पथों सहित ग्रामीण व अन्य विभागों के स्वामित्व वाले पथों को अधिग्रहित करते हुए कुल 785 कि०मी० पथों के उन्नयन के साथ-साथ पूर्व से निर्मित 1,200 कि०मी० पथों के मजबूतीकरण/Riding Quality में सुधार कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही, 35 Standalone उच्चस्तरीय Flyovers/ROBs के निर्माण की योजना है।

137. वर्ष 2026–27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6 हजार 601 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण कार्य

138. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 1,644 कि०मी० पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में नए पथों के निर्माण हेतु 1,000 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

139. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढीकरण योजना के तहत पाँच वर्ष एवं उससे पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त लगभग 15,000 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण कराते हुए ग्रामीण आबादी का सरकारी कार्यालय, स्कूल/कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, बाजार तक आवागमन सुगम बनाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अबतक 5,400 कि०मी० पथों के सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में पथों के सुदृढीकरण हेतु 1,600 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

140. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 122 अदद पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में पुलों के निर्माण कार्य हेतु 730 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

141. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 620 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

142. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026–27 में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5 हजार 81 करोड़ 74 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

नागर विमानन

143. **अध्यक्ष महोदय,** बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU किया गया है, जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट सुविधाओं का विस्तारीकरण के साथ रनवे की लंबाई को 9,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट तक करने की योजना है।
144. **आदरणीय महोदय,** राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की राजधानी से अधिकतम दूरी वाले क्षेत्र को वायु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साहेबगंज जिला अन्तर्गत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण प्रस्तावित है।
145. राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सस्ते दर पर Air Ambulance सेवा दिनांक 28.04.2023 से 24X7 संचालित की जा रही है। सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों को सुलभ हो इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की कटौती की गयी है। वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए इस योजनान्तर्गत **10 करोड़** रुपये का बजट उपबंध किया गया है।
146. **अध्यक्ष महोदय,** नागर विमानन हेतु वर्ष 2026—27 में **138 करोड़ 63 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।**

ऊर्जा

147. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 35 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026—27 में इस योजनान्तर्गत **5 हजार 405 करोड़** रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

148. **मान्यवर**, झारखण्ड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। साथ ही, कृषि उपभोक्ताओं हेतु नये विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है। पतरातु में चार हजार मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट में नवंबर, 2025 में 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है।
149. **मान्यवर**, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में **450 करोड़ रुपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
150. **आदरणीय महोदय**, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य अनुदान के रूप में **800 करोड़** के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।
151. **अध्यक्ष महोदय**, वित्तीय वर्ष 2026–27 में झारखण्ड बिजली वितरण निगम तथा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम को क्रमशः 600 करोड़ और 1,500 करोड़ रुपये ऋण स्वरूप दिये जाने हेतु बजटीय उपबंध का प्रस्ताव किया गया है।
152. **अध्यक्ष महोदय**, विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 2026–27 में **11 हजार 197 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट** प्रस्तावित है।

उद्योग

153. **अध्यक्ष महोदय**, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) मंच के माध्यम से झारखण्ड ने 01 लाख 24 हजार 230 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनसे इस्पात, ऊर्जा, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में लगभग 45 हजार रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।

154. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में 5,000–6,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से PMEGP योजना के तहत रोजगार सृजित होने की संभावना है।
155. **अध्यक्ष महोदय,** विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में 20 हजार करोड़ का निवेश लाया जाएगा, जिससे राज्य के लगभग 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
156. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1,800 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक लगभग 1,125 मीट्रिक टन रॉ तसर का उत्पादन हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में रेशम प्रक्षेत्र में 1,800 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य है।
157. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड में कुटीर उद्योग के सतत विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का संचालन कराया जा रहा है।
158. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए वर्ष 2026–27 में उद्योग विभाग के लिए 541 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

भवन निर्माण विभाग

159. **आदरणीय महोदय,** राज्य की राजधानी में झारखण्ड पुलिस हेतु 80 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

160. प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राँची में श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के 155 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से बन रहे नये भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे जुलाई, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
161. वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु भवन निर्माण विभाग के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

नगर विकास एवं आवास

162. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत अब तक झारखण्ड राज्य के लिए कुल 2 लाख 11 हजार 10 आवासीय इकाई स्वीकृत है, जिसमें से 1 लाख 42 हजार 333 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 51 हजार 638 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
163. अध्यक्ष महोदय, राँची में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर संबंधित कुष्ठ रोगियों को आवास आवंटित कर दी गयी है।
164. अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास अंतर्गत कुल 36 हजार 202 निर्माणाधीन आवास एवं भागीदारी में किफायती आवास अंतर्गत कुल 36 हजार 740 निर्माणाधीन आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।
165. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत स्वीकृत आदित्यपुर शहरी जलापूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना, हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना एवं चास सेप्टेज प्रबंधन योजना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

166. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026–27 में 09 निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को मंजूरी देने एवं 06 लिगेसी अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। साथ ही, 27 निकायों के लिए Used Water Management परियोजना को मंजूरी देने का लक्ष्य है।
167. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026–27 में रामगढ़ शहर के लिए इंटरशेप्शन एवं डायवर्सन तकनीक पर आधारित 310 करोड़ 11 लाख की लागत से 40 एम०एल०डी०एस०टी०पी० के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। धनबाद शहर के लिए 858 करोड़ 86 लाख की लागत से 192 एम०एल०डी०एस०टी०पी० के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। फुसरो नगर परिषद में 14 एम०एल०डी०एस०टी०पी० के अधिष्ठापन का कार्य मार्च, 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
168. **अध्यक्ष महोदय,** राँची ट्रांसपोर्ट नगर फेज-2 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर में ISBT का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
169. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026–27 में 14 जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है।
170. **वर्ष 2026–27 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3 हजार 919 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।**

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य

171. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026–27 में पर्यटन के क्षेत्र में राँची जिलान्तर्गत दशम जलप्रपात में ग्लास ब्रिज का निर्माण, जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज एवं रोप वे का निर्माण तथा हुण्डरू जलप्रपात रोप वे का विकास कार्य कराया

जाएगा। रामगढ़ जिलान्तर्गत रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ-साथ पतरातु में स्काइवॉक एवं पतरातु जलाशय में सोलर बोट तथा फ्लोटिंग रेस्टोरेन्ट का अधिष्ठापन किया जाएगा।

172. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2026-27 में लातेहार जिलान्तर्गत नेतरहाट में कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास वॉच टॉवर का निर्माण एवं मैगनोलिया प्वाइंट में स्काइवॉक का निर्माण कराया जाएगा। देवघर जिलान्तर्गत पुनासी डैम का पर्यटकीय विकास, **पलामू जिलान्तर्गत मलय डैम का पर्यटकीय विकास,** चतरा जिलान्तर्गत कोलेश्वरी पहाड़ में रोप वे का विकास एवं खूँटी जिलान्तर्गत पेरवाघाघ जलप्रपात तथा पांडू-पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कार्य कराया जाएगा।
173. **अध्यक्ष महोदय,** खनन पर्यटन विकसित करने के लिए ITDCL तथा CCL के मध्य MoU किया गया है।
174. **अध्यक्ष महोदय,** विभाग द्वारा वर्तमान में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र एवं 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा नये डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है।
175. **माननीय महोदय,** गिरिडीह जिलान्तर्गत बेंगाबाद प्रखण्ड के मौजा कर्णपुरा में आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गयी है। कमार दुधानी, दुमका स्थित आउटडोर स्टेडियम में 08 लेन का आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गयी है।
176. **माननीय महोदय,** राँची के बिरसा मुण्डा एथलेटिक्स स्टेडियम, खेलगाँव के फुटबॉल ग्राउण्ड का उन्नयन कार्य की स्वीकृति दी गई है। सिल्ली प्रखण्ड में संचालित आवासीय तीरंदाजी क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में 25 शैय्या वाले खेल छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

177. **महोदय**, सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन कई जिलों में निरीक्षण भवन, रेस्ट हाउस, परिसदन आदि निर्मित हैं, जिसके परिसर में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर Way-Side Amenities के निर्माण कार्य हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
178. **माननीय महोदय**, सरकार राज्य में झारखण्ड संगीत नाटक अकादमी, झारखण्ड ललित कला अकादमी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी का गठन नियमावली अधिसूचित कर दिया गया है।
179. **माननीय महोदय**, राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र, सरायकेला के सुचारु रूप से संचालन के निमित्त कार्यकारी एवं स्थायी समितियों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी है। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं झारखण्ड सरकार के बीच 5 वर्षों के लिए MoU किया गया है।
180. **वर्ष 2026–27 में पर्यटन विभाग के लिए 361 करोड़ 67 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।**

सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस

181. **अध्यक्ष महोदय**, वित्तीय वर्ष 2026–27 में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 174 करोड़ 95 लाख 07 हजार रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।
182. **अध्यक्ष महोदय**, आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके-द्वार पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 5,226 शिविर आयोजित कर 11 लाख 85 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है।
183. **अध्यक्ष महोदय**, झारखण्ड स्टेट Data Center 2.0 स्टेट ऑफ आर्ट डाटा सेंटर है, जो सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल करते हुए बनाया गया है। राज्य

सरकार के 245 applications में से 180 production and 65 staging environment में स्टेट डाटा सेंटर में होस्टेड हैं।

184. वर्ष 2026–27 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 328 करोड़ 99 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

185. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 में झारखण्ड के विभिन्न शहरों की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने एवं आवागमन को सुचारु बनाने के उद्देश्य से नए-नए यातायात थानों की स्थापना की जाएगी।
186. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद से लगभग 60 करोड़ रुपये की सहायता केन्द्र सरकार से प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि से राज्य के उग्रवाद प्रभावित District of Concern पश्चिमी सिंहभूम तथा 03 Legacy and Thrust जिला यथा— बोकारो, चतरा तथा लातेहार के विकास के माध्यम से इन्हें वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराया जायेगा।
187. अध्यक्ष महोदय, राज्य के अफीम उत्पादक जिले से अफीम की खेती के विनिष्टिकरण के लिए अभियान चलाकर जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है तथा कृषकों को इसके बदले वैकल्पिक खेती के विकल्प दिये जा रहे हैं।
188. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के काराओं में मोबाईल फोन के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से 5G Cell Phone Jammer तथा Mobile Phone detector का क्रय कर अधिष्ठापन किया जायेगा।

189. **आदरणीय महोदय**, राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा शमन निधि मद में क्रमशः **720 करोड़** रुपये तथा **180 करोड़** रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
190. वर्ष 2026–27 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत हेतु प्रस्तावित बजट **900 करोड़** रुपये का है।
191. वर्ष 2026–27 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कुल **11 हजार 38 करोड़ 53 लाख** रुपये का बजट प्रस्तावित है।

योजना एवं विकास

192. **अध्यक्ष महोदय**, जिलों की स्थानीय आवश्यकता एवं Missing Critical Gap को पूरा करने हेतु **जिला स्तर योजना अनाबद्ध निधि** के माध्यम से जिलास्तर पर छोटी-छोटी योजनाएं ली जाती हैं, जो एक ही वित्तीय वर्ष में समाप्त हो सके। जिला योजना अनाबद्ध निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में **405 करोड़** रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।
193. **अध्यक्ष महोदय**, जिलास्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभाग के माध्यम से Innovative Jharkhand योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत **78 करोड़** रुपये का बजटीय उपव्यय प्रस्तावित है।
194. **अध्यक्ष महोदय**, विकास के लिए योजनाओं के अवधारण और सूत्रण के साथ-साथ विभिन्न प्रक्षेत्रों में क्रिटिकल गैप पूरा करने में योजना एवं विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। **वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 539 करोड़ 94 लाख** रुपये का बजट प्रस्तावित है।
195. **अध्यक्ष महोदय**, योजना एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कुल

13 विभागों का आउटकम बजट इस सदन के पटल पर लगातार छठी बार प्रस्तुत किया जा रहा है।

196. **अध्यक्ष महोदय**, आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य का कुल योजना आकार **1 लाख 891 करोड़** रुपये है, जिसमें 13 विभागों की योजनाओं का आउटकम बजट की राशि **62 हजार 329 करोड़ 04 लाख** रुपये है, जो योजना बजट का लगभग **62** प्रतिशत है।
197. **अध्यक्ष महोदय**, आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर **बाल बजट** भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने का उद्देश्य राज्य में बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 138 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल **10 हजार 7 सौ 93 करोड़ 16 लाख** रुपये की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 10.7 प्रतिशत है।
198. **अध्यक्ष महोदय**, आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर **जेन्डर बजट** भी तैयार किया गया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेन्डर बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल **34 हजार 2 सौ 11 करोड़ 27 लाख** रुपये की राशि उपबंधित की गई है।
199. **अध्यक्ष महोदय**, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमने सदन के पटल पर केवल आय–व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है, अपितु यह समस्त

झारखण्डवासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को भी वाणी दी है। महोदय, कठिनाईयाँ और विषम परिस्थितियाँ मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित और संकल्पित करती हैं।

200. **अध्यक्ष महोदय**, मैं अपना बजट अभिभाषण इस सदन को इस कविता के साथ समर्पित कर रहा हूँ कि :—

नई दिशा, नई हो रही पहल
खुशहाल, जल—जमीन—जंगल
अंतिम व्यक्ति तक जा रहे
खुशियों का दीप जला रहे
हर हाथ को काम दिला रहे
मंईयां का सम्मान बढ़ा रहे
चलो बढ़ाएं मिलकर सब हाथ
एक होने के संकल्प के साथ
हर कौम को साथ बढ़ाएंगे
विकसित झारखण्ड बनाएंगे।

जय हिन्द !

जय झारखण्ड !

जोहार !

